(क) क्या बिहार के कटिहार जिले में आबादपुर में कोई उप-डाक घर नहीं है जबकि पश्चिम बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर और माल्दह जिलों के निकट स्थित है जो कि सीमान्त जिले है ;

(ख) क्या प्रशासकीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण से डाक तथा तार सेवायें यहां के लिए बहुत आवशयक है ; और

(ग) यदि हां, तो आबादपुर में उप डाकघर कब तक खोला जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस) : (क) जी हां ।

(ख) यहां विभागेतर शाखा डाकघर की व्यवस्था है जिससे उपयुक्त डाक सुविधाएं मिल जाती हैं । प्रशासनिक महत्व के स्थानों पर घाटा उठाकर भी तार और टेलीफोन सेवाएं देने के लिए सरकार उदार नीति अपना रही है । सामान्य इलाकों के मामलों में 5000 से अधिक आबादी वाले स्थानों और पहाड़ी या पिछड़े इलाकों में 2500 से अधिक आबादी वाले स्थान में घाटा उठा कर भी, कम से कम आप की शर्तों के अनुसार, तार सुविधाएं देने के बारे में विचार किया जाता है । उदारीकृत शर्तों के अधीन भी, आबादपुर इन सेवाओं की व्यवस्था के लिए उचित नहीं ठहरता ।

(ग) विभागेतर शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ा कर उसे विभागीय उप डाकघर बनाने का पहले औचित्य नहीं ठहरता थ । इस मामले की पुनः जांच की जा रही है ।

स्वीडन से विदेशी सहायता

1504. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को स्वीडन से कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस रूप में; और

(ग) उसकी शर्तें क्या हैं ।

स्वास्थ्य, और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय भेज दिया जाएगा ।

Debts on Industrial Workers

1505. SHRI KARPOORI THAKUR: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the burden of personal debts on industrial workers has increased during the past few years;

(b) if so, the steps being taken by Government to make them free from these debts; and

(c) outlines of the Scheme being formulated by Government to check the exploitation of industrial labourers by the usurers in future?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (c). Comparable figures indicating increase or decrease of indebtedness are not available. According to a Pilot Survey conducted at Delhi recently, the comparative figures of average indebtedness for working

class family at Delhi for 1958-59 (Family living result) and December, 1976 (Pilot Survey result) are as follows:—

Period	Average indebtedness for working class family
	Rs.
(i) Family living Survey 1958-59	451.00
(ii) Pilot Survey on indebtedness-December, 1976	1800.00

Labour Bureau, Simla, has currently in hand indebtedness survey at 25 selected industrial centres. It would be advisable to await the results of these surveys before coming to any firm conclusion whether there has been any increase or decrease of indebtedness during the past few years.

Government are also considering the question of promoting a suitable legislation to secure to industrial workers relief from the burden of indebtedness.

बंधुआ मजदूरी के पुन: चालू होने का समाचार

1506. **श्री यशवन्त शर्मा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं जिनमें देश में बंधुआ मजदूरी को पुन: प्रभावी होने के संकेत मिलते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे समाचार देश के किन भागों से प्राप्त हो रहे हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या प्रभावी कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रममंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) ऐसी कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में कलेक्टरों को यह निदेश दिए गए हैं कि स्वाधीन किए गए बंधित श्रमिकों को चालू प्लान स्कीमों और कार्यक्रमों, जिनमें भूमि संरक्षण, सिंचाई कार्य, समाज कल्याण कार्य, जन-जाति तथा हरिजन कल्याण कार्यक्रम सम्मिलित हैं, में लगाकर यथा शीघ्र पुन: बसाया जाए ।

31 मई, 1977 तक स्वाधीन किए गए 95,993 बंधित श्रमिकों में स 23691 को सरकारी विभागों में रोजगार देकर, कृषि भमि और मकानों की जगहों का आवंटन करके, दूध देने वाले पशुओं, मेढ़ो और बढ़ई के औजारों को खरीदने के लिए ऋणों की व्यव था करके तथा वाधीन कराए गए श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा तथा नि:शुल्क छात्रावास सुविधाओं का प्रबन्ध करके पुन: बसा गया है । रा ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ब्याज की विभिन्न दरों पर ऋण भी दिए

Medical Colleges in the Country

1507. DR. BIJOY MONDAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state: